

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास डॉ० अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -108/2023

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2023/122

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भवरुराम पुत्र भागुराम जाति-जाट,निवासी-मोकलपुर, तहसील-मेड़ता		1. हरदीनराम पुत्र भोलाराम 2. गोपालराम पुत्र भोलाराम फौत के का०मु० 2/1 रामनिवास पुत्र गोपालराम 2/2 श्रवणराम पुत्र गोपालराम 2/3 कमलादेवी पुत्री गोपालराम 3. गोकुड़ी पत्नी लिखमाराम सभी जाति-जाट,निवासीगण- मोकलपुर,तहसील-मेड़ता 4. तहसीलदार,मेड़ता ।

उपस्थिति:-

1. अपीलान्त की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या-1,2/1 से 2/3 की ओर से वकील श्री भरतकुमार ओझा।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री डूंगरराम।

:: निर्णय ::

दिनांक :- 12/09/2023

अपीलान्त द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार, मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या 520/1972 प्रार्थीगण भागुराम वगैरा पुत्र भोलाराम में भूमि का धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा के संबंध में तहसीलदार,मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.1972 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 27.06.2023 को प्रस्तुत की गई हैं। अपीलान्त की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा बावजूद तामिल इस अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लिया हैं।

वकील अपीलान्त ने अपील के साथ मयाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्त ने मियाद के बिन्दु पर प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 5 लिमिटेशन में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे बहस में यह कथन किया कि मौजा मोकलपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 42 रकबा 75 बीघा 19 बिस्वा भूमि भागु पुत्र भोला जाट के कब्जे काश्त व खातेदारी की रहती आई हैं,उक्त भूमि के वर्तमान में खसरा नम्बर 196,197,198,199,200 मौजा मोकलपुर में स्थित हैं। उक्त भूमि के बंटवाड़ा के संबंध में माननीय तहसीलदार,मेड़ता को क्षेत्राधिकार नहीं होने के बावजूद अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बंटवाड़ा के आदेश पारित कर दिया,जो विधि विरुद्ध हैं।



२
कलक्टर नागौर

वादग्रस्त भूमि पर आज दिन भी अपीलांट ही काबिज काश्त हैं। हाल ही में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन प्रवेश कर अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तो अपीलांट ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तब रेस्पोजेन्ट ने कहा कि उक्त भूमि का बंटवाड़ा करवा रखा है तथा हमारे भी नाम से खातेदारी दर्ज है, तब अपीलांट ने इस संबंध में जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चूंकि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के रहने वाले सीधे साधे अनपढ़ काश्तकार होने से उन्हें कानून की बारिकियों की जानकारी नहीं होने से जमाबंदी को देखने का काम ही नहीं पड़ा था, इसलिए पूर्व में उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी।

अधीनस्थ न्यायालय में हमारे पिता भागूराम को गलत रूप से गुमराह करके उसकी खातेदारी की भूमि को हड़प करने की नियत से गलत रूप से हरदीनराम, लिखमाराम, गोपाल ने अपने नाम बंटवाड़ा करवा लिया जबकि विधि अनुसार इस भूमि का बंटवाड़ा उनके मध्य नहीं हो सकता था, केवल रजिस्ट्री बेचान से ही हस्तान्तरण हो सकता था, क्योंकि वह प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार दर्ज नहीं थे। तहसीलदार, मेड़ता द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह बंटवाड़ा किया है, जो गैर कानूनी है। तहसीलदार, मेड़ता के उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 19.06.2023 को प्रथम बार हुई तथा अपीलांट को यह जानकारी नहीं थी कि तहसीलदार के आदेश की अपील कहाँ होगी। इस जानकारी के लिए सलाह करने पर यह ज्ञात हुआ कि अपील न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर में पेश होगी, तब गरीब काश्तकार होने से रुपये-पैसे की व्यवस्था करके दिनांक 23.06.2023 को अपीलांट नागौर आया तथा अपील तैयार करवायी गई। दिनांक 24.06.23 व 25.06.2023 का राजकीय अवकाश होने से अपील दिनांक 27.06.2023 को पेश की गई है, जो उक्त आदेश की जानकारी होते ही माननीय न्यायालय में पेश की गई है, जो अन्दर मयाद शुमार की जावें।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि हमने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अपीलांट का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र भी पेश किया है, जिस पर माननीय न्यायालय को विश्वास करके अपील अन्दर मयाद शुमार की जानी चाहिए। वैसे भी तहसीलदार, मेड़ता का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया गया आदेश है, इसलिए गैर कानूनी आदेश के विरुद्ध अपील पेश करने में मयाद का बिन्दू लागू भी नहीं होता है। इसलिए निवेदन है कि अपील देरीना पेश करने में लगे समय को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार किया जाकर अपील का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 3/1 ने जबाब बहस में यह निवेदन किया कि जैर अपील आदेश में दर्ज भूमियां पैत्रिक भूमियां थी तथा भागूराम बड़े भाई होने से तथा कर्ताखानदान की हैसियत से काम करने वाले व्यक्ति के नाम से खतौनी में सारी भूमियां दर्ज हो जाने से वे भूमियां अकेले उसकी नहीं हो जाती हैं। तहसीलदार, मेड़ता ने बंटवाड़ा की आराजी को पुस्तैनी माना है तथा यह भूमि भागूराम, हरदीनराम, गोपाल, लिखमाराम के सहअभिधारी की भूमि होने से तहसीलदार, मेड़ता द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा किया है, जो राज्य सरकार के परिपत्रों के तहत विधिवत किया गया है।



कलक्टर नगौर

(राजस्व अपील संख्या 108/23 भंवरुराम बनाम हरदीनराम)

//3//

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 का यह भी तर्क है कि अपीलाधीन प्रकरण बंटवाड़ा होकर प्रकरण संख्या 520/1972 दर्ज होकर पूर्ण सुनवाई होकर अपीलांट के पिता स्वयं के द्वारा बंटवाड़े का आवेदन पेश करना व उनके द्वारा बंटवाड़ा की लिखत का स्टाम्प खरीद करना तथा 51 वर्षों से राजस्व रेकॉर्ड अलग2 दर्ज होना तथा मामला 51 साल पूर्व का है जिसकी जानकारी अपीलांट को व उसके पिता को शुरू से ही रहती चली आई है। चूंकि इन्होंने ही आगे होकर बंटवाड़ा करवाया है तथा बाद बंटवाड़ा अपीलांट के पिता ने व अपीलांट ने इतने लम्बे समय तक बंटवाड़ा के हिसाब से बिघोड़िया चुकाई है,जिससे स्पष्ट है कि इस बंटवाड़ा की जानकारी अपीलांट व उसके पिता को तथा तमाम पक्षकारों को शुरू से रहती चली आई है। अनपढ़ काश्तकार अनपढ़ होने की वजह से अपने काश्तकारी की भूमियां अर्थात् खेतों की जमीनों को पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा सावधानी से ध्यान रखता है और उपयोग उपभोग में लेता है,जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को व अपीलांट के पिता को शुरू से ही इस बंटवाड़ा की जानकारी थी। इस प्रकार अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज की जावें।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 2/1 से 2/3 के अभिभाषक ने दौराने बहस अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान वकील उभय पक्षकारान द्वारा पेश की गई उपरोक्त बहस पर मनन किया । पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मेड़ता से प्राप्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कार्यालय तहसीलदार,मेड़ता के प्रकरण संख्या 520/1972 अन्वान भागूराम वगैरा में आदेश दिनांक 21.06.1972 जारी कर भागूराम,हरदीनराम,गोपाराम,लिखमाराम के बीच प्रश्नगत भूमि का बंटवाड़ा कर राजस्व रेकार्ड में खाते दर्ज का आदेश दिया है। इस पत्रावली में भागूराम द्वारा कय स्टाम्प तीन रूपये पर बंटवाड़ा इकरारनामा लिखा गया है,जो दिनांक 18.04.1972 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है,का इस आदेश में अंकन है,जिससे यह प्रकट है कि इस बंटवाड़ा की जानकारी भागूराम को शुरू से ही थी । अपील के साथ प्रस्तुत ग्राम मौकलपुर की जमाबंदी नकल खाता संख्या 647/568 सम्वत् 2076 के अवलोकन से उक्त खाते में काश्तकार का नाम भंवरुराम पुत्र भागूराम हिस्सा पूर्ण जाति-जाट देह खातेदार दर्ज है राहिन(पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा,मौकाला के दर्ज है। इस जमाबंदी के राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपने खाते की भूमि पर एक्सिस बैंक से ऋण प्राप्त किया है,इसलिए अपीलांट को ऋण पत्रावली तैयार करते समय तथाकथित बंटवाड़ा की पूर्ण रूप से जानकारी हो गई थी। इस प्रकार तथाकथित बंटवाड़ा की जानकारी भागूराम को शुरू से ही तथा उनके बेटे अपीलांट को भी खसरा नम्बर 198 की जमीन पर बैंक ऋण लिया तथा उसके कागजात तैयार किये उस समय हो चुकी थी परन्तु उन्होंने इन सब तथ्यों को छुपाते हुवे इस अपील की विलम्ब अवधि को क्षमा करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र में सही तथ्य प्रकट नहीं किये हैं एवं न ही शपथ-पत्र में उनका अंकन किया है। अब लगभग 51 वर्ष बाद इस बंटवाड़ा को चुनौती दी है। इस प्रकार के इस असाधारण विलम्ब अवधि को क्षमा करने के पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना-पत्र में अपीलांट द्वारा अंकन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मयाद पेश नहीं की गई है। इसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 520/1972 में अपीलांट पक्षकार संयोजित नहीं है,उसके बावजूद उनके द्वारा यह अपील पेश की गई, जिसके लिए उनके द्वारा दफा 96 सी.पी.सी के प्रावधानों के तहत अपील पेश करते समय



कलेक्टर नार्नाल

(राजस्व अपील संख्या 108/23 भंवरुराम बनाम हरदीनराम)

//4//

प्रार्थना-पत्र पेश करना था जो पेश नहीं किया है। अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम मौकलपुर के खाता संख्या 647/568 के अनुसार खसरा नम्बर 198 एक्सिस बैंक शाखा मौकाला के राहिन दर्ज है, परन्तु बैंक अधिकारी जरिऐ सम्बन्धित बैंक को इस प्रकरण में पक्षकार रेस्पोंडेन्ट संयोजित नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत मयाद बाहर होने से तथा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से तथा प्रकरण प्रस्तुत करते समय धारा 96 सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति के प्रार्थना-पत्र का अभाव होने से अपील अपीलांत खारिज योग्य है। इसलिए अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड मय निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया ।




(डॉ० अमित यादव)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर